



छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, सेक्टर - 19, नया रायपुर (छ.ग.) 492002

Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 2085/तक.सू.अ./छ.ग.प.सं.मं/2018
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 30/5/2018

श्री विनोद चावड़ा, अधिवक्ता,
आत्मजा-स्व. गोविंदभाई चावड़ा,
जियो:म्-ब्रम्हशाला, एमआईजी 706,
पदमनाभपुर, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 21/05/2018, इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 25/05/2018.

-----: 000 :-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई जानकारी/दस्तावेज कुल 02 पृष्ठों की सत्यापित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पता


श्री आर.पी. तिवारी

अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य अभियंता (प्रभार)

छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

पर्यावास भवन, सेक्टर-19,

नया रायपुर (छ.ग.) 492002


30/5/2018
(ए.क. गेडाम)

जन सूचना अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)

५५

R.NO-800 Date-23-04-2018

श्री विनोद चावडा, अधिवक्ता, रूम: डा.वि.जी. 706, जानी टंकी के पास, विश्वदीप स्कूल के पीछे, पद्मनाभपुर, दुर्ग का पत्र दिनांक 18-04-18 मैसर्स बलदेव एलायज प्राइवेट लिमिटेड, के विषयांकित विधिक अंग्रिम सूचना आव्यत् पत्र प्राप्त पत्र हुआ है। कृपया अवलोकनार्थ प्रकृत है।



छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

S.E. मल्लोडम

26/4/18

SE (B)

26/4/18

कृपया पत्र-निवेदन का अवलोकन हो, प्रकृत पत्र पर Law Institute के टीम से ज्ञान प्रस्तावित है।

अतिरिक्त

Pl. proceed

SE (B) Lawiforum

27/4

As per the records of documents available, the Industry had filed and given the 'Consent' as per the requisite documents mandatory for the 'Consent Renewal' from time to time. The issue regarding the cheating and fraud on part of the Directors is the internal matter of the Management of the Industry. And Regarding this, they had already approached the Hon'ble National Company Law Tribunal at Mumbai. The Hon'ble NCLT direct as "whereby the Respondents including RS are hereby directed not to create

सत्यापित

[Signature]

शाखा तकनीकी/रायपुर - 225/III क्रमांक (121)
विषय मेसर्स बलदेव एलायज प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा, जिला-रायपुर

(*)

any further third-party rights over R1 Property sold to R5 until further orders. Hence, they had not stayed the operations of the Industry.

And Pollution Board (CECB) is the regulatory Authority over the industry running the State of Chhattisgarh, in terms of Pollution as under environmental laws.

Henceforth the Board had not dishonored any law and issued the 'Consent letter' as per the provisions under the Water Act, 1974 & Air Act, 1981 and after fulfilling other required eligibility.

for your kind Perusal & necessary Actions.



उ.प्र. पर्यावरण संरक्षण मंडल

S.E.(B)

सुप्रीम कोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित

Karnal
27/4/15

~~श्री. अ. अ. अ.~~

1/5

As per the advice of the Law intern, we shall maintain status quo until further directions / decisions from the court/war.

1/5

SE(B)

SE(S)

Sharma

1/5

01/5

सत्यापित

(Handwritten signature)

(जन सूचना अधिकारी)

उ.प्र. पर्यावरण संरक्षण मंडल